श्रीमती राजेन्द्र कुमारी और एक अन्य

बनाम

श्रीमती शांता त्रिवेदी और अन्य

20 फरवरी, 1989

[मुरारी मोहन डट और टी. के. थॉममेन, न्यायाधिपतिगण

मोटर वाहन अधिनियम, 1939:-धारा 93, 94 और 95-मोटर दुर्घटना - घातक - दावा - मुआवजे की तर्कसंगतता – की गणना - बीमा कंपनी की देयता स्वीकार की गई- क्या बीमा कंपनी पॉलिसी दाखिल करने के लिए बाध्य है।

अपीलकर्ता 1 और 2 क्रमशः मृतक की पत्नी और बेटी हैं जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब वह एक किराए की कार में यात्रा कर रहे थे, जो एक ट्रक से टकरा गई। वह मौके पर मर गया। उनकी मृत्यु के समय वह 25 वर्ष के थे।

अपीलकर्ताओं ने 1 लाख रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की। न्यायाधिकरण का निष्कर्ष था कि दुर्घटना लापरवाही से कार चलाने के कारण हुई थी। बिना कारण बताए, न्यायाधिकरण ने कार के मालिक और ट्रक चालक के

खिलाफ केवल 10,000 रुपये देने का फैसला सुनाया, और 4,000 रुपये की सीमा तक बीमा कंपनी की देनदारी का भी आकलन किया।

फैसले के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने दिए गए मुआवजे की पर्याप्तता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की। कार के मालिक ने आपत्ति दर्ज करायी। उच्च न्यायालय ने फैसले की पुष्टि की और अपील और प्रति-आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुआवजा न्यायसंगत और उचित था।

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। अपीलकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया कि मुआवजे के रूप में न्यायाधिकरण के केवल 10,000 रुपये के फैसले की पुष्टि करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया

1. अपीलकर्ता मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये की राशि के हकदार हैं। इस राशि में से बीमा कंपनी, यानी प्रतिवादी नंबर 4; 4,000 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और अन्य प्रतिवादी संयुक्त रूप से और अलग-अलग अपीलकर्ताओं को शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। [766 सी]

2. यह सच है कि मृतक अपनी मृत्यु के समय एक छात्र था, लेकिन वह अपने पिता का व्यवसाय भी देख रहा था और लगभग 1 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा था। मामूली गणना पर भी, मृतक का अपने परिवार के प्रति योगदान 500 रुपये प्रति माह यानि कि प्रति वर्ष 6,000 रु. से कम नहीं हो सकता है। यदि जीवन की सामान्य अवधि 60 वर्ष मानी जाए, तो वह 35 वर्ष और जीवित रहेगा। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को एक लाख रुपये से अधिक से वंचित किया गया है और तदनुसार, मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये का उनका दावा काफी उचित था। अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे की राशि को केवल 10,000 रुपये निर्धारित करना न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों के लिए उचित नहीं था। [765 बी-डी]

3. जैसा कि कानून भौतिक समय पर था, ऐसे मामले में बीमा कंपनी की अधिकतम देनदारी केवल 4,000 रुपये थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी कि बीमा कंपनी की वैधानिक देनदारी केवल 4,000 रुपये थी, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया था। इन परिस्थितियों में, पॉलिसी दाखिल करना बीमा कंपनी के लिए बाध्य नहीं था। [766 ए-बी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जुगल किशोर एवं अन्य, [1988] एसीजे 270, अंतर किया गया।

इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि डिक्रीटल राशि का भुगतान दो महीने के भीतर किया जाना चाहिए और डिफ़ॉल्ट के मामले में, वसूली तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। [766 डीआई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2086(एन) / 1978

राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. सिविल विविध अपील संख्या 73/1970, में के निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.1976 से।

सी एम लोढ़ा और एच.एम. सिंह अपीलकर्ताओं की ओर

बी.आर. सभरवाल, पी.आर. रामाशेष और एच. वाही, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दत्त, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

यह अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, उदयपुर द्वारा दिए गए फैसले की पुष्टि करने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है।

3 और 4 दिसंबर, 1966 के बीच की रात में, अपीलकर्ता नंबर 1 के पति और अपीलकर्ता नंबर 2 के पिता, हरि सिंह मृतक ने राजस्थान

महिला परिषद से संबंधित एक एम्बेसडर कार राजस्थान के उदयपुर से मध्य प्रदेश के कांगेटी स्थित अपने पैतृक गांव जाने के लिए किराए पर ली। जब कार उदयपुर से 21 मील दूर चली गई तो सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। वह फिसल गई और एक पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना के परिणामस्वरूप, हरि सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई और शंकर लाल नामक व्यक्ति, जो उसी कार में यात्रा कर रहा था और हरि सिंह का दोस्त था, को कुछ चोटें आईं।

अपनी मृत्यु के समय, हरि सिंह केवल 25 वर्ष के थे। वह अपने पीछे अपनी पत्नी, अपीलकर्ता संख्या 1 जो केवल 18 वर्ष की थी और अपीलकर्ता संख्या 2, उनकी बेटी, जो तब केवल एक बच्चा था, छोड़ गए।

अपीलकर्ताओं ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, उदयपुर के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें मुआवजे के रूप में 1 लाख रु. रुपये की राशि का दावा किया गया।

न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस दुर्घटना के परिणामस्वरूप हरि सिंह की मृत्यु हुई, वह कार की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं के 1 लाख रुपये के मुआवजे के दावे के मुद्दे का निपटारा इस प्रकार कर दिया:

> "1967 के केस नंबर 3 के दावेदारों ने 1 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया है जो अत्यधिक प्रतीत होता है।

मेरी राय में 10,000 रुपये की राशि पर्याप्त होगी। मुद्दे का निर्णय तदनुसार किया जाता है।"

न्यायाधिकरण ने कोई कारण नहीं बताया है कि अपीलार्थी के 1 लाख रूपये के मुआवजे के दावे को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता था। इस स्तर पर, यह कहा जा सकता है कि बीमा कंपनी का मामला जो न्यायाधिकरण के समक्ष विपरीत पक्ष संख्या 3 था, उसकी देनदारी केवल 4,000 रुपये की राशि तक थी। बीमा कंपनी की देनदारी से संबंधित न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया मुद्दा नंबर 7 नीचे दिया गया है:

"7: क्या विपरीत पक्ष संख्या 3 की देनदारी प्रत्येक मामले में 4,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती।"

अंक संख्या 7 पर न्यायाधिकरण का निष्कर्ष इस प्रकार है:

"दावेदारों के विद्वान वकील ने माना कि बीमा कंपनी का दायित्व प्रत्येक मामले में 4 हजार रूपये से अधिक नहीं हो सकता है। तदनुसार मुद्दे का निर्णय विपक्षी पार्टी संख्या 3 के पक्ष में किया जाता है।"

उक्त निष्कर्षों पर, न्यायाधिकारण ने राजस्थान महिला परिषद और ट्रक के चालक सहित विपक्षी दलों के खिलाफ बीमा कंपनी की देनदारी का आकलन करते हुए केवल 4,000 रुपये की सीमा तक करते हुये अपीलकर्ता के पक्ष में 10,000 रुपये का पंचाट पारित किया।

न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि की पर्याप्तता को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की। कार की मालिक राजस्थान महिला परिषद की ओर से भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उच्च न्यायालय ने, जैसा कि पहले ही कहा गया है, फैसले की पुष्टि की और अपील और प्रति-आपत्ति को खारिज कर दिया। अतः विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री लोढ़ा ने जो पहला मुद्दा उठाया है, वह यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे के रूप में केवल 10,000 रुपये के न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करना उचित नहीं था। अपीलकर्ता क्रमांक 1 के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि मृतक के पिता के पास एक डेयरी फार्म, एक पोल्ट्री फार्म, एक आटा मिल और एक कृषि फार्म था। मृतक व्यवसाय देखता था और उसकी मासिक आय लगभग 1,000 रुपये थी और उक्त आय में से लगभग 700 रुपये खर्च हो जाते थे और कुल बचत केवल 300 रुपये प्रति माह थी। इस साक्ष्य के विपरीत, उत्तरदाताओं द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने मात्रा के संबंध में न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि की। मुआवज़े की राशि इस प्रकार देखी गई:

"दावेदारों द्वारा दिए गए सबूतों से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हरि सिंह अपनी मृत्यु के समय वास्तव में एक छात्र थे और हो सकता है कि जब भी उन्हें समय मिलता, वे अपने पिता की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की देखभाल करते थे, जो राजेन्द्र कुमारी के अनुसार अभी भी चल रही हैं। उन्होंने खुद को पारिवारिक व्यवसाय के लिए समर्पित कर दिया था और शिक्षा पर निर्भर होने के बावजूद उनकी कोई संभावना नहीं थी। विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभों का अनुमान लगाते समय, नुकसान और आय में उतार-चढ़ाव की आकस्मिकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यवसाय में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में हम जानते हैं कि एक युवा राजपूत लड़की के लिए अपने पति को खोना एक ऐसी घटना है जिसकी भरपाई कोई भी पैसा नहीं कर सकता है, फिर भी मामले की परिस्थितियों में, हम यह नहीं पाते कि न्यायाधिकरण द्वारा तय मुआवजे की राशि बहुत अधिक या बहुत कम थी। हमें लगता है कि यह उचित मुआवजे का प्रतिनिधित्व करता है।"

हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को समझने में असमर्थ हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई मुआवजे की राशि काफी पर्याप्त थी। उच्च

न्यायालय ने अपीलकर्ता नंबर 1 के इस साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया है कि उसके पति की मासिक आय 1,000 रुपये थी। यह सच है कि अपनी मृत्यु के समय हरि सिंह एक छात्र थे, लेकिन वह अपने पिता का व्यवसाय भी देख रहे थे और 1,000 रुपये प्रति माह कमाते थे। हरि सिंह की आय के बारे में अपीलकर्ता नंबर 1 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

मामूली हिसाब से भी हरि सिंह का अपने परिवार के प्रति योगदान 500 रुपये प्रति माह से कम नहीं हो सकता था; यानी 6,000 रुपये प्रति वर्ष। जीवन की सामान्य अवधि को 60 वर्ष मानते हुए; हरि, सिंह अगले 35 वर्ष जीवित रहते। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को एक लाख रुपये से अधिक से वंचित किया गया है और, तदनुसार, मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये का उनका दावा काफी उचित था। अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे की राशि को केवल 10,000 रुपये निर्धारित करना न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों के लिए उचित नहीं था।

अगला प्रश्न बीमा कंपनी की देनदारी के बारे में है, यहां प्रतिवादी संख्या 4 है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के समक्ष स्वीकार किया कि बीमा कंपनी की देनदारी 4,000 रुपये से अधिक नहीं है। वास्तव में, जैसा कि कानून भौतिक समय पर था, ऐसे मामले में बीमा कंपनी की अधिकतम देनदारी केवल 4,000 रुपये थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी कि बीमा कंपनी की वैधानिक देनदारी केवल 4,000 रुपये थी, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया था। इस न्यायालय में पहली बार, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 मुआवजे की पूरी राशि के लिए उत्तरदायी है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री लोढ़ा ने आग्रह किया कि यह प्रतिवादी नंबर 4 पर निर्भर है कि वह न्यायाधिकरण के समक्ष बीमा की पॉलिसी दाखिल करे ताकि यह दिखाया जा सके कि 4,000 रुपये तक की वैधानिक देनदारी के अलावा, प्रतिवादी नंबर 4 पर वैधानिक देनदारी से अधिक पॉलिसी के तहत कोई और देनदारी नहीं थी। विवाद के समर्थन में, विद्वान वकील द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जुगल किशोर और अन्य, [1988] एसीजे 270 में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है। उस मामले में यह माना गया है कि जहां संबंधित बीमा कंपनी दावा याचिका लेना चाहती है क्योंकि उसकी देनदारी वैधानिक देनदारी से अधिक नहीं है, उसे अपने बचाव के साथ बीमा पॉलिसी की एक प्रति दाखिल करनी चाहिए। हमारी राय में यह निर्णय, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि बीमा कंपनी की देनदारी केवल 4,000 रुपये तक बढ़ी है। इन परिस्थितियों में, हमें नहीं

लगता कि पॉलिसी दाखिल करना बीमा कंपनी पर निर्भर था। तदनुसार, अपीलकर्ताओं की ओर से दिया गया तर्क खारिज किया जाता है।

परिणामस्वरूप, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता मुआवजे के रूप में रूपये 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) की राशि के हकदार हैं। उक्त राशि में से, बीमा कंपनी, प्रतिवादी संख्या 4, केवल 4,000 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और राजस्थान महिला परिषद सहित प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 संयुक्त रूप से और अलग-अलग अपीलकर्ताओं को शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रतिवादी को तारीख से दो महीने के भीतर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, उदयपुर में अपनी संबंधित देनदारियों की सीमा तक डिक्रीटल राशि जमा करनी होगी; चूक होने पर, डिक्रीटल राशि या उसका उतना हिस्सा जो बकाया रहेगा, वसूली तक बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को ऊपर बताई गई सीमा तक संशोधित किया गया है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.एन. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।